बेशर्म भाजपाई टूटी सड़कों पर निकाल रहे तिरंगा यात्रा

महंगाई, जलभराव से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाटक

2001 तक संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराना अपराध था

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : स्वतंत्रता दिवस अभी बहुत दूर है लेकिन जनता का ध्यान बांटने और उसे मूर्ख बनाने के लिए भाजपा ने 1 अगस्त को पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा की शुरूआत की।यह यात्रा दो हफ़्ते तक चलेगी। फ़रीदाबाद ज़िले में इसकी शुरुआत बल्लभगढ़ से क्षेत्रीय भाजपा विधायक और मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने की। तिरंगे की आड़ में तमाम अनैतिक गतिविधियों के लिए आरएसएस बदनाम है।

अंधेर नगरी के दलाल

फ़रीदाबाद और समूचे हरियाणा के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बारिश ने तमाम सड़कों की बखिया उधेड़ दी है। फ़रीदाबाद में टूटी सड़कों पर पानी भरने की वजह से हादसे हो रहे हैं। जल भराव की वजह से कई कॉलोनियाँ, अफ़सरों के आवास पानी में डूबे हुए हैं। करोड़ों रूपये नालों की सफ़ाई पर खर्च कर दिए गए लेकिन शहर के नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है।

सड़कों को बनाने वाले ठेकेदार या तो भाजपा नेताओं के रिश्तेदार हैं या भाजपा नेताओं को हर टेंडर पर कमीशन मिला हुआ है। मामूली बारिश में सड़कों का इतना बुरा हाल होने के लिए कमीशनखोर मंत्री और भाजपा नेता सीधे ज़िम्मेदार हैं। टूटी सड़कों पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर का बयान 1 अगस्त को मीडिया में पढ़ने को मिला। गूजर ने कहा कि जो सड़कें तारकोल से बनी थीं वो इस बारिश में टूट गईं लेकिन सीमेंट वाली सड़कें नहीं टूटीं। मंत्री के बयान का मतलब और मकसद आसानी से समझा जा सकता है।

शहर में जल संकट से भाजपा नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। सरकारी पानी बेचने और चोरी में उनकी संलिप्तता सामने आ रही है। आये दिन सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन भाजपा नेता उन प्रदर्शनों का संज्ञान तक नहीं लेते। पिछले दिनों एक भाजपा पार्षद को रात में सेक्टर 25 के बूस्टर पंप पर एमसीएफ के जई के साथ शराब पार्टी करते फ़ेसबुक लाइव में देखा गया।

पेट्रोल-डीजल सौ रूपये लीटर जा पहुँचा है और महंगाई उच्चतम स्तर पर है। इसका सबसे ज़्यादा असर असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों और मेहनतकश लोगों पर पड़ रहा है। कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, वे अभी भी बेरोज़गार बैठे हैं।

भाजपा की केंद्र सरकार के पास इन समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जनता का ध्यान बँटाने के लिए उसके पास तमाम तरह के नाटक खेलने का पर्याप्त अनुभव है। इस काम में अपने राजनीतिक मुखौटे भाजपा की मदद के लिए आरएसएस ने तमाम फ्रंटल संगठन बनाये हुए हैं जिनका काम है देशभक्ति के नाम पर कार्यक्रमों का आयोजन। यह तिरंगा उसी नाटक का हिस्सा है।

हैरानी यह है कि बल्लभगढ़ के जो लोग अभी कल तक बिगड़ती क़ानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे थे, जलभराव की शिकायत कर रहे थे, पेयजल संकट का रोना रो रहे थे, वे तिरंगा यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर और मूलचंद शर्मा को माला ऐसे पहना रहे थे जैसे देश को इन लोगों ने ही आज़ाद कराया था।

किसान नेता समझ गए चाल

किसान नेता आरएसएस की इस चाल को फ़ौरन समझ गए। उन्होंने बयान जारी किया कि जनता और किसान इस तिरंगा यात्रा का विरोध न करे।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने हरियाणा के किसानों से अपील की है कि वे भाजपा की तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करें। एसकेएम ने दावा किया कि यह किसानों को भड़काने और बदनाम करने की 'कुटिल चाल' है।

करीब 40 किसान संगठनों के संयुक्त मंच एसकेएम ने रविवार को एक बयान में कहा कि अन्य कार्यक्रमों और भाजपा-जजपा का विरोध जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि भाजपा की हरियाणा इकाई द्वारा प्रस्तावित तिरंगा यात्रा मुख्य रूप से किसनों को भड़काने और उन्हें बदनाम करने के लिए है। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों से आह्वान करता है कि वे इसे भाजपा की कुटिल चाल के तौर पर देखें और उनकी राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में गंदी चाल को सफल नहीं होने दें।

आरएसएस और तिरंगा

आरएसएस मुख्यालय नागपुर और उसके फ्रंटल संगठनों के दफ़्तरों में 2002 से तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की शुरुआत हुई। 2001 तक संघ मुख्यालय और उसके अन्य दफ़्तरों में तिरंगे की जगह भगवा ध्वज फहराया जाता था।

संघ मुख्यालय पर हुई एक घटना जो लोग भूल चुके हैं, उसे याद दिलाना ज़रूरी है। यह घटना नागपुर एफआईआर नंबर 176 के नाम से मशहूर है।

अगस्त 2013 को नागपुर की एक निचली अदालत ने वर्ष 2001 के एक मामले में दोषी तीन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इन तीनों आरोपियों बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी का जुर्म तथाकथित रूप से सिर्फ इतना था कि वे 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशमीबाग स्थित आरएसएस मुख्यालय में घुसकर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में शामिल थे। संघ इस कोशिश पर इतना तिलमिला गया कि तीनों युवकों पर मुकदमा (एफ नंबर 176) दर्ज हो गया और 12 साल तक वो लड़के संघ के निशाने पर बने रहे।

इसके बाद कांग्रेस ने इस मामले को उठाना शुरू कर दिया। संघ बैकफुट पर आ गया। आरएसएस यह समझ गया कि इस मुकदमे का हवाला देकर उसकी देश के प्रति निष्ठा पर सवाल खड़े किये जायेंगे। इसके बाद आरएसएस ने वो शिकायत वापस ले ली और संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वाले वो लड़के बरी हो गए। इसके बाद संघ ने तिरंगे को लेकर ऐसा प्रचार किया कि अब ऐसा लगता है कि देश को संघ ने आज़ाद कराया था।

एक और घटना राजस्थान में हुई थी। उदयपुर कोर्ट पर 14 दिसंबर 2017 को भगवा झंडा आरएसएस के संगठनों से जुड़े उन्मादियों ने फहराया था। कोर्ट पर तिरंगा पहले से ही लहरा रहा था। संघी आतंकियों ने अदालत से तिरंगा उतारकर भगवा झंडा फहरा दिया था। दरअसल, एक मुस्लिम की हत्या में शंभूनाथ रैगर को गिरफ़्तार किया गया था। उसी घटना को संघ के स्वयंसेवकों ने उन्माद में बदला और जबरदस्त साम्प्रदायिक हिंसा की।

पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय सेना के सूबेदार वीर अब्दुल हमीद की शहादत को हर साल 26 जनवरी को यूपी के कासगंज में वीर अब्दुल हमीद चौक पर याद किया जाता है। 26 जनवरी 2018 को जब यह कार्यक्रम चौक पर चल रहा था तो उसी समय आरएसएस से जुड़े संगठनों के युवक तिरंगा यात्रा लेकर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ उत्तेजक साम्प्रदायिक नारे लगाए। इसके बाद वहाँ ज़बर्दस्त हिंसा हुई। इस घटना में यूपी सरकार के संघी मानसिकता वाले वो अधिकारी और कासगंज का पुलिस प्रशासन भी शामिल था, जिसने तिरंगा यात्रा को उस चौक तक आने की इजाज़त दी थी।

इन घटनाओं से साफ़ है कि आरएसएस और भाजपा तिरंगे की आड़ में तमाम साम्प्रदायिक गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं।

2021 के ग्रैजुएट को नौकरी नहीं, निजी बैंक का विज्ञापन

एचडीएफ़सी बैंक ने कहा कि इस वर्ष पास युवक आवेदन नहीं करें

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : यह मामला गंभीर है। लेकिन भारत के किसी अख़बार में आपने यह खबर अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। जिसकी आशंका थी, वही हुआ। पहले ही यह चर्चा चल पड़ी थी कि कम से कम भारत का प्राइवेट सेक्टर 2021 में ग्रैजुएट, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास करने वालों के प्रमाणपत्रों और डिग्रियों को मान्यता नहीं देगा। अब वही हो रहा है। इस खबर के साथ लगी फ़ोटो को गौर से देखिए।

देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है अनेक पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में हैं तो अनेक अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं ऐसे में यदि कोई रोजगार देने वाला यह शर्त लगा दे कि जिसने कोरोना काल के वर्ष 2021 में परीक्षा पास की है तो उसे योग्य नहीं माना जाएगा तो यह बेहद शर्मनाक और गंभीर मामला है ।

एचडीएफसी बैंक ने 3 अगस्त को नौकरियों के लिए दिए गए विज्ञापन में आवश्यक योग्यता ग्रेजुएट मांगी है लेकिन स्पष्ट किया कि जिन्होंने 2021 में ग्रेजुएशन किया है उसे मान्य नहीं किया जाएगा।

मतलब इस वर्ष जिन्हें डिग्री मिली है वह रोजगार के लिए मान्य नहीं है। देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष आनलाइन परीक्षा आयोजित की थी और यह निर्णय सरकार के निर्देशानुसार लिया गया था अब प्राइवेट सेक्टर ऐसी परीक्षा में पास हुए लोगों को अयोग्य माना रहा है तो इस मामले में सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए अन्यथा यह देश की युवा पीढ़ी के साथ अन्याय होगा।

एक तरफ़ तो यह स्थिति है, लेकिन शिक्षा के धंधे में इस समय जो घटित हो रहा है, भारत का मीडिया उसे छिपा रहा है।

भारत में पिछले दो दशकों से स्कूल के बाहर बच्चों को पढ़ाने और यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के मकसद से कोचिंग करने वाली कंपनियों का कारोबार कितनी तेजी से बढ़ा है हम सबने देख लिया है। स्कूलों में पढ़ाई और शिक्षकों के खराब स्तर के साथ ही इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट संस्थानों में दाखिले के लिए बढ़ती गलाकाट होड़ ने कोचिंग के कारोबार को फलने-फूलने में भारी मदद पहुंचाई है। कोटा की पूरी अर्थव्यवस्था कोचिंग के कारोबार पर ही खड़ी है। दिल्ली के मुनरीका, लक्ष्मीनगर, मुखर्जी नगर और कालू सराय इलाकों में आईआईटी और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए सैकड़ों कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं।

पिछले कुछ सालों से कोरोना के कारण ऑनलाइन एजुकेशन का जोर बहुत बढ़ गया है। इसे देखते हुए ही मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश कर रही हैं। कोरोना महामारी में डिजिटल शिक्षा की दुनिया में क्रांति आ गई है और इस महामारी ने डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन डिजिटल पढ़ाई को प्राइवेट कंपनियाँ मान्यता देनें में आनाकानी कर रही हैं। एचडीएफ़सी बैंक के विज्ञापन ने इसकी पुष्टि कर दी है।

आज देश के कोचिंग कारोबार पर विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। बायजू भारतीय कम्पनी

बस नाम के लिए ही है। 2018 से ही बायजू में दिग्गज निवेश कंपनी टेन्सेंट, बीसीसीआई, न्यूयॉर्क की जनरल अटलांटिक, सिकोया कैपिटल, मार्क एंड चेन जुकरबर्ग फिलेन्थ्रोपिक इनिशिएटिव का निवेश बढ़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले ही बायजू में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब 1000 करोड़ रुपये निवेश किया।

इसी निवेश के कारण उसने भारत में परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली सबसे बड़े स्तर की कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज का अधिग्रहण कर लिया है।

पिछले छह महीने में बायजू ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों के अधिग्रहण पर 2 अरब डॉलर (करीब 15 हजार करोड़ रुपये) से ज्यादा खर्च किए हैं, अनएकेडमी (unacdemy) इंडिया में फेसबुक सहित अन्य कंपनियों ने 715 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पर, सवाल यही है कि क्या भारत में डिजिटल पढ़ाई को प्राइवेट सेक्टर मानेंगे ?